

खबर संक्षेप



आईआईटी दिल्ली में शम्भूनाथ यूनिवर्सिटी के छात्रों लहराया परचम

शहडोल। पंडित शम्भूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के मत्स्य विज्ञान विभाग ने एक बार फिर राष्ट्रीय फलक पर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। विभाग के तीन होनहार स्तिारों शोभाथी राजपाल पाटले सहित विद्यार्थी कैवल्या प्रजापति और अंजलि पटेल का चयन देश के सर्वोच्च संस्थान आईआईटी दिल्ली में प्रतिष्ठित अनुसंधान परियोजना (इंटर्नशिप) के लिए हुआ है। यह सफलता कोई तुक्का नहीं, बल्कि विभाग में चल रहे गुणवत्तापूर्ण शोध का परिणाम है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष भी यहाँ के दो छात्रों ने इसी तरह की प्रतिष्ठित इंटर्नशिप हासिल की थी। लगातार दूसरे साल आईआईटी जैसे संस्थानों में जगह बनाना यह साबित करता है कि शहडोल का मत्स्य विज्ञान विभाग अब राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान नर्सरी बन चुका है। चयनित छात्र अब दिल्ली की अत्याधुनिक लैब्स में लिबनेलॉजी एवं टॉक्सिकोलॉजी जैसे जटिल विषयों पर विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के साथ कार्य करेंगे। इस गौरवशाली उपलब्धि पर कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे छात्रों ने अपनी प्रतिभा से विश्वविद्यालय और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस सफलता का श्रेय विभागाध्यक्ष प्रो. अमित निगम के मार्गदर्शन और सहायक प्राध्यापक डॉ. वंदना राम के सटीक निदेशन को जाता है। मत्स्य विज्ञान विभाग की इस हेट्टिक ने जिले के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए सफलता का एक नया पैमाना तय कर दिया है। विश्वविद्यालय परिवार ने चयनित छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आज जिला विकास सलाहकार एवं प्रबंध समिति की बैठक

शहडोल। जिले के प्रमारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में तहसील ब्योहारी के बाणसागर सर्किट हाउस में जिला विकास सलाहकार समिति एवं जिला प्रबंध समिति की बैठक 8 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों, सड़क निर्माण, चिकित्सा विभाग सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति के सचिव एवं सदस्यों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

मकान सूचीकरण कार्य का अपर कलेक्टर ने किया निरीक्षण



शहडोल। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी सरोधन सिंह ने जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम गोडनटोला, चम्बोडी में किए जा रहे मकान सूचीकरण गणना कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर फील्ड में कार्यरत प्रमाणकों एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति का सत्यापन किया तथा मोबाइल एप के माध्यम से डाटा फीडिंग की प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी मकान अथवा व्यक्ति सूचीकरण से वंचित न रहे। उन्होंने सभी प्रगणकों को प्राप्त डाटा का कॉस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने तथा तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर संबधित अधिकारी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री आज रहेंगे शहडोल जिले के प्रवास पर



शहडोल। मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रमारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल 8 मई 2026 को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री प्रातः 8:30 बजे रीवा से देवलौढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रातः 9:30 बजे देवलौढ़ पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस बाणसागर में प्रातः 10 बजे से जिला प्रबंध समिति की बैठक लेंगे तथा प्रातः 11 बजे जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक लेंगे। बैठकों के पश्चात उप मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे देवलौढ़ से रीवा के लिए प्रस्थान करेंगे।

खुद को वकील बताने वाला दबंग दे रहा आगजनी की धमकी, 3 दिन का अल्टीमेटम!

शारदा खदान में सफेदपोश गुंडागर्दी

शहडोल।

जिले के सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत शारदा ओसीएम में इन दिनों विकास और खनन के काम से ज्यादा दबंगई और वसूली का शोर है। आर.के. अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में घुसकर जिस तरह से उत्पात मचाया गया और कंपनी के बड़े अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई, उसने कोयलांचल की कानून व्यवस्था की धजियां उड़ा दी हैं। खुद को कानून का जानकार बताने वाला एक कथित वकील अब सरंआम खदान को फूंकने और खूनखराबे की बात कर रहा है।

वर्दी और कानून को खुली चुनौती

हैरानी की बात यह है कि कानून की दुहाई देने वाला व्यक्ति ही कानून का मजाक उड़ा रहा है। शिकायत पत्र के अनुसार, आरोपी ने कंपनी प्रबंधन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 3 दिन में मेरे आदमियों को नौकरी नहीं मिली, तो खदान की गाड़ियों में आग लगा दूंगा और दफ्तर के किसी भी कर्मचारी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दबंगई यहीं नहीं रुकी, उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह खुद वकील है और पुलिस या कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे।

जीएम के सामने सरंआम गाली-गलौज

घटना गुरुवार, 7 मई 2026 की दोपहर करीब 1:45

ग्राम पंचायत खैरहा में सामुदायिक भवन बना उगाही का केंद्र



शहडोल।

जिले की जनपद पंचायत सोहागपुर की ग्राम पंचायत खैरहा इन दिनों भ्रष्टाचार और तानाशाही का चारागाह बन गई है। सरपंच और सचिव की जुगलबंदी ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर सरकारी खजाने को निजी जागीर समझ लिया है। हद तो तब हो गई जब भ्रष्टाचार के आरोपों पर सचिव चंद्रिका शर्मा ने निर्लज्जता की सारी हदें पार करते हुए कह दिया कि चार-पांच सौ का कोई घोटाला नहीं होता। सचिव महोदय शायद सत्ता के नशे में यह भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम और वित्तीय नियमावली के अनुसार, शासन के खजाने से एक रुपये का भी अनैतिक आहरण गबन की श्रेणी में आता है। धारा 92 के तहत लोक धन की हानि पहुंचाना दंडनीय अपराध है। सचिव का यह बयान न केवल उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है, बल्कि यह सीधे तौर पर जिला प्रशासन और ऑडिट व्यवस्था को खुली चुनौती है। अगर 500 रुपये घोटाला नहीं है, तो क्या सचिव महोदय बताएंगे कि भ्रष्टाचार की न्यूनतम सीमा उन्होंने क्या तय कर रखी है। 3500 रुपये किराया और 5000



बजे की है। बताया जा रहा है कि ग्राम बकहि निवासी त्रिलोचन मेहरा (जो पेशे से वकील बताता है) अपने साथ 6 से 10 गुणों को लेकर सब-एरिया ऑफिस में धमक गया। कंपनी के जनरल मैनेजर महेश्वर यादव द्वारा अमलाई थाने में दी गई लिखित शिकायत के मुताबिक, त्रिलोचन मेहरा

ने दफ्तर में घुसते ही अभद्र भाषा और गंदी-गंदी गालियों की बौछार कर दी। आरोपी ने न केवल काम रुकवाने की कोशिश की, बल्कि कर्मचारियों की लिस्ट मांगते हुए जबरन अपने आदमियों को नौकरी पर रखने का फरमान सुना दिया।

थैलेसीमिया के श्राप से कब मिलेगी मुक्ति दिशा वेलफेयर ने छेड़ी जंग

शहडोल।

जब एक नन्हा मासूम पहली सांस लेता है, तो मां-बाप उसके सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के नसीब में सपनों की जगह सिर्फ हर महीने चढ़ने वाली खून की बोतलें और आयरन की कड़वी दवाइयां लिखी होती हैं। 8 मई यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उन पत्थर हो चुकी नसों और डबडबाई आंखों का हिसाब मांगने का दिन है, जो सिस्टम की लापरवाही और सामाजिक अज्ञानता की भेंट चढ़ रहे हैं।

जिंदगी और मौत के बीच 15 दिन का फासला

थैलेसीमिया मेजर के शिकार बच्चों के लिए जीवन किसी खोफनाक युद्ध से कम नहीं है। शरीर में हीमोग्लोबिन न बनने के कारण हर 15 से 20 दिन में इन मासूमों को खून चढ़ाना पड़ता है। रक्त केंद्रों के बाहर अपने जिगर के टुकड़े के लिए एक-एक यूनिट खून की भीख मांगते माता-पिताओं का

दरद किसी को सुनाई नहीं देता। ऊपर से महंगी चिलेशन थेरेपी और दवाइयों का खर्च मध्यमवर्गीय परिवारों की कमर तोड़ देता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूमियत उम्रकैद की यह सजा काटती रहेगी?

लापरवाही से मिल रहा श्राप

यह बेहद शर्मनाक है कि आधुनिक चिकित्सा के दौर में भी जांच रिपोर्टों में लापरवाही और डॉक्टरों की अनदेखी के चलते बच्चे इस लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हो रहे हैं। किसी लैब या डॉक्टर की एक छोटी सी चूक एक पूरे परिवार को ताउम्र का नरक परोस देती है।

कुंडली नहीं, ब्लड रिपोर्ट मिलाओ

समाज के इस गहरे जख्म को भरने के लिए दिशा वेलफेयर ने अब आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। संस्था ने सरकारी और चिकित्सा तंत्र को घेरते हुए मांग की है कि विवाह से पूर्व थैलेसीमिया टेस्ट को कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में ही स्क्रीनिंग को डॉक्टरों के लिए अनिवार्य नियम बनाया जाए। हर जिले में मुफ्त इलाज और दवाइयों के लिए सरकारी थैलेसीमिया केंद्र खोले जाएं।

जनजागरूकता और रक्तदान का महासंग्राम

8 मई को इस मिशन को धार देने के लिए दिशा वेलफेयर द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से लालपुर में विशाल कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और फील्ड वर्कर्स को जागरूक किया जाएगा। साथ ही, एक विशाल रक्तदान शिविर भी लगंगा ताकि किसी बच्चे की सांस खून की कमी से न रुके। आओ जागरूक बनें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां कोई भी बच्चा खून की बोतलों का मोहताज न रहे।

पुर्तगालियों को धूल चटाने वाली अभयारानी की शौर्यगाथा से गुंजा कन्या महाविद्यालय



शहडोल।

अजेय पुर्तगाली सेना के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाली महान वीरांगना महारानी अबक्का बाई की 500वीं जन्मजयंती पर शहडोल का छात्राओं ने उनके अदम्य साहस का हंकार भरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) द्वारा शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में रानी अबक्का के रणकौशल और बलिदान की गुंज सुनाई दी। मुख्य वक्ता डॉ. कुमुद सांड्या ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब दुनिया पुर्तगाली आक्रमणकारियों के नाम से कांपती थी, तब भारत की इस शेरनी ने उन्हें बार-बार युद्ध के मैदान में पटखनी दी। उन्होंने कहा,

योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महारानी ने न केवल सीमा की रक्षा की, बल्कि मंदिरों और तीर्थ स्थलों का कार्याकल्प कर भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा। उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक ऐसा सुदृढ़ राज्य बनाया, जिसकी विरासत आज भी कर्नाटक के लोकगीतों और यक्षगान में जीवंत है।

कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन और वीरांगना के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। संचालन साक्षी सिंह ने किया और आभार प्रदर्शन महाविद्यालय इकाई मंत्री जिया दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभाग छात्रा प्रमुख अंजलि पांडेय, जिला संयोजक अमन त्रिपाठी, भूमिका द्विवेदी, प्रेरणा द्विवेदी, अंशिका मिश्रा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और छात्राएं उपस्थित रहीं। परिषद के इस आयोजन ने छात्राओं के भीतर राष्ट्रवाद और स्वाभिमान की एक नई लौ जला दी है।

संयुक्त निदेशक जन गणना ने मकान सूचीकरण कार्य का किया निरीक्षण

शहडोल।

संयुक्त निदेशक जनगणना जय शहाजत पुरी ने जनगणना 2027 अंतर्गत धनपुरी में किये जा रहे मकानसूचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मकान अथवा व्यक्ति सूचीकरण से वंचित न रहे तथा सभी प्रगणकों को प्राप्त डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करते हुए कार्य में प्रगति लाएं।



संयुक्त निदेशक ने घर-घर जाकर मकानसूचीकरण हेतु लोगों से चर्चा कर जनगणना कार्य में सहयोग करने हेतु अपील की। उन्होंने कहा कि मकानसूचीकरण हेतु प्रगणकों को सटीक एवं सत्यता के साथ जानकारी दें। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक श्री आशीष श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी सरोधन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



खबर संक्षेप

दुकान में पानी भरने से हुआ लाखों का नुकसान



ब्यूहारी-। नगर परिषद के अंतर्गत चुंगी नाका में जोरदार बारिश में दुकानों में पानी भर गया। चुंगी नाका में स्थित खाद बीज की दुकान में पानी भर गया अमन बीज भंडार के संचालक अगम कुमार गुप्ता ने बताया कि शाम 4:00 बजे हुई बारिश में दुकान में रखा हुआ सल्फर, जिंक, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक एवं बी ज़प्रोमो सब पानी में भीग गया शाम को हुई जोरदार बारिश में मेरे दुकान में रखा हुआ लगभग डेढ़ लाख का सामान खराब हो गया बेमौसम हुई इस बारिश में दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति दिलाया जाना आवश्यक है।

जलभराव की समस्या का करें स्थायी समाधान कटनी। निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने आगामी वर्षा काल को दृष्टिगत रखते हुए नगर में जलभराव की समस्या की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण कर समस्या का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगमायुक्त द्वारा गठित टीमों की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि विगत वर्ष जिन क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई थी, उन स्थलों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर ली जाए। ताकि इस वर्ष नगर में विगत वर्ष जैसी जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने वार्डों में चिन्हित जलभराव स्थलों का स्थल निरीक्षण कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आवश्यक निर्माण एवं सफाई कार्य वर्षा पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही अथवा उदासीनता के कारण किसी क्षेत्र में जलभराव की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जनसुविधा और प्रशासनिक सुगमता को केंद्र में रखकर होगा प्रशासनिक पुनर्गठन : मिश्रा



मध्यप्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की जिला एवं तहसील स्तरीय बैठक संपन्न

उमरिया। उमरिया में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की जिला एवं तहसील स्तरीय बैठक जिला पंचायत के बांधवगढ़ सभागार में आयोजित हुई। बैठक में आयोग के सदस्य पूर्व आईएसएस एफ एन मिश्रा, मुकेश शुक्ला तथा आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने प्रशासनिक पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी साझा की इसके साथ ही उन्होंने बैठक के अंत में अधिकारियों से पुनर्गठन से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए तथा उन्हें आयोग के समक्ष रखने पर सहमति प्रदान की। एस एन मिश्रा ने पीपीटी के माध्यम से बताते हुए स्पष्ट किया कि पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नई प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण नहीं, बल्कि जनता को सरल, त्वरित और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है। इसके तहत तहसील, विकासखंड और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं, मुख्यालयों तथा पद संरचना का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि भौगोलिक दूरी, यातायात सुविधा, जनसंख्या घनत्व, आदिवासी क्षेत्र, प्राकृतिक सीमाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को आधार बनाकर निर्णय लिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि कलेक्टर को कार्यालय में किसी संस्था,समिति अथवा जनप्रतिनिधि से कोई सुझाव या प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन प्रस्तावों की स्वयं जांच कराने,आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के अनुरूप उन्हें पूर्ण करवाने तथा तत्पश्चात अपनी टीम के साथ आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। मुकेश शुक्ला ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल और प्रश्नावली व्यवस्था शुरू की है, जिससे आम नागरिक, सामाजिक संस्थाएं और जनप्रतिनिधि सीधे अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर व्यापक बैठकें, विभागीय समीक्षा

और फॉलोअप प्रक्रिया भी तय की गई है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक निर्णय लिए जा सकें।उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आप सब अपने क्षेत्र के वांछित प्रशासनिक सुधारों को कलेक्टर महोदया के माध्यम से आयोग तक पहुंचाएं।उन्होंने कहे कि आयोग सभी सुझावों की गहन समीक्षा करने के उपरांत अंतिम सुझाव शासन को प्रस्तावित करेगा। आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासनिक युक्तियुक्तकरण से सरकारी सेवाओं की पहुंच गांवों तक आसान होगी। लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और आर्थिक खर्च दोनों कम होंगे। नई प्रशासनिक व्यवस्था से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और जनसुनवाई प्रणाली अधिक मजबूत होगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और सेवा वितरण प्रणाली में तेजी आएगी। बैठक में बताया गया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रश्नावली वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से जारी कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति, संस्था, श्रमिति अथवा जनप्रतिनिधि यदि किसी प्रशासनिक इकाई में युक्तियुक्तकरण, विलोपन या नवीन सृजन संबंधी प्रस्ताव देना चाहता है, तो वह पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जिनकी आयोग स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि उमरिया जैसे जनजातीय एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में पुनर्गठन से विकास कार्यों में गति आएगी, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। आयोग सचिव अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, वन मण्डलाधिकारी विवेक सिंह, उप संचालक बीटीआर योहान कटारा, अपर कलेक्टर पी के सेनगुप्ता, संयुक्त कलेक्टर एवं प्रशासनिक पुनर्गठन जिला नोडल अधिकारी अमित सिंह, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सहित जिलाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना पर गंभीर आरोप

कमीशन लेकर करवाते हैं रेत चोरी

ब्यूहारी- विकासखंड के अंतर्गत रेत चोरी और कमीशन के तार रामनगर ब्लाक के जनपद सदस्य राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना के बारे में छेत्र के लोग बताते हैं कि इनके सहित इनका पूरा परिवार ट्रैक्टर के माध्यम से रेत चोरी में संलिप्त है। इनके भतीजे छोटे भाई ये स्वयं रेत के इन खेल में शामिल है। सूत्रों की माने तो विगत दिनों जब से रेत में वन विभाग और सीन गड्डियाल ने कार्यवाही की तो वहां से रेत निकलना बंद हो गया—अब वहां से रेत निकालने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा

रहा। तो ये जहां किसानों के खेत है वहां ट्रैक्टरों के माध्यम से जबरन रेत निकालने का कार्य संचालित करना चाहते है—किसान अपने खेत से रेत इन्हें नहीं निकालने दे रहे है तो दबाव बनाने की नियत से ये शिकायत करने निकले है। इन्हें किसान ट्रैक्टर से रेत निकालने की अनुमति दे दे तो— इनकी शिकायत खत्म हो जाती है। इनके भाई भतीजे सब अवैध उत्खनन मैं सम्मिलित हैं यह निकलना बंद हो गया—अब वहां से रेत खुद तो बालू का धंधा करवाते हैं करते हैं



ऊपर से यह कमीशन भी मांगते हैं कि हम जनपद सदस्य हमको नहीं मिलेगा तो हम

धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे हमरा दारू और गाड़ी का खर्चा कैसे चले कभी यह दारू वालों को परेशान करने लगते हैं ठेकेदारों को लगाकर परेशान करने लगते हैं जो खदान से गाड़ियां आती है उनको भी परेशान करवाने लगते हैं तोडफोड़ करवाते हैं गुंडे रीवा से बुलाकर के मारपीट करवाते हैं अवैध वसूली करवाते हैं गाड़ियों से एंट्री मांगते हैं 10 से 15 गाड़ी बालू यह खुद अपने ग्रह ग्राम बंसी पर में स्टॉक करके रखे हैं इनका ट्रैक्टर बांसी से दिन रात चलता है और उनके साथ

एक पुष्पेंद्र बैस है मझटोलवा का यह अभी कई बार जेल जा चुका है कई अपराध इसके नाम पर हैं यह भी अवैध वसूली में सम्मिलित है यह सबसे लगा लगाकर धमकी देता है कि हम चलाएंगे पैसा किसी को नहीं देंगे जबरदस्ती करेंगे नहीं तो कलेक्टर ऑफिस जाएंगे जमीन भी नहीं पाओगे रात में जेसीबी से खनन कर ता है छेत्र के लोगों ने जनपद सदस्य और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग खनिज विभाग एवं मप्र शासन से की है।

ठेकेदार की लापरवाही से अधूरी गौशाला, सड़कों पर मर रही गाय

धनपुरी। नगर में गौवंशों की बढहाल स्थिति अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सड़कों पर घूम रही गायें आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं, लेकिन उनके संरक्षण के लिए बनाई जा रही गौशाला खुद अधूरी पड़ी है। इस पूरे मामले में नगरपालिका और ठेकेदार—दोनों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। नगर के विभिन्न वार्डों में लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन गौवंशों के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई। नतीजतन, गायें खुले में सड़कों पर भटक रही हैं और तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर घायल हो रही हैं। कई मामलों में आवारा कुत्तों के हमले से भी उनकी मौत होने की बात सामने आई है।

एक साल से अधर में लटका निर्माण

नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए की लागत से गौशाला निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था। यह निर्माण कार्य पूर्व में बंद हो चुकी धनपुरी यूजी माईंस परिसर में किया जा रहा है, ताकि आवारा गौवंशों को सुरक्षित आश्रय मिल सके। हालांकि, यह महत्वाकांक्षी परियोजना पिछले लगभग एक वर्ष से अधूरी पड़ी है। ठेकेदार द्वारा काम बंद कर दिया गया है, लेकिन इसे दोबारा शुरू कराने के लिए कोई ठोस पहल नहीं दिख रही।



भुगतान लापरवाही—क्या है वजह?

स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि कहीं ठेकेदार को भुगतान नहीं मिलने के कारण काम रुका हुआ है। यदि ऐसा है, तो नगरपालिका को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं, अगर ठेकेदार की लापरवाही से कार्य अधूरा छोड़ा गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही—यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

जिम्मेदारों की चुप्पी पर नाराजगी

नगरवासियों का आरोप है कि नगरपालिका अधिकारी और इंजीनियर इस मुद्दे पर गंभीर नहीं

हैं। यदि समय रहते निर्माण कार्य की निगरानी और ठेकेदार से जवाब-तलब किया जाता, तो गौशाला आज तक तैयार हो चुकी होती।

बिना आश्रय, बढ़ता खतरा

गर्मी, सर्दी और बारिश—हर मौसम में बिना आश्रय के रह रहे गौवंशों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। दुर्घटना के बाद भी समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं होने से उनकी जान पर बन आती है।

मांग: जल्द पूरा हो निर्माण, तय हो जिम्मेदारी

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि गौशाला निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही, ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्थानीय परिवाद समिति का गठन

श्रीमती सुमिता शर्मा बनीं अध्यक्ष

राजनगर। कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में अनुपपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर अनुपपुर द्वारा महिलाओं के कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिरोषण) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति का पुनर्गठन किया गया है। यह समिति जिले के विभिन्न विभागों और कार्यस्थलों पर होने वाले लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों की सुनवाई कर उनका त्वरित निराकरण करेगी। नवनि्युक्त समिति में सामाजिक और कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि शिकायतों का न्यायोचित समाधान हो सके। अध्यक्ष श्रीमती सुमिता शर्मा, सदस्य (विधि) जनदीश प्रसाद पाण्डेय एलएल बी. एवं पूर्व सदस्य, बाल कल्याण समिति, सदस्य श्रीमती रोशनी पनाडिया स्नातकोत्तर एवं एलएल बी. (पुष्पराजगढ), पदेन सदस्य श्रीमती मंजूषा शर्मा सहायक संचालक,

महिला एवं बाल विकास, सदस्य सुश्री सीमा गांजू परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास। ज़ारी आदेश के अनुसार, यह समिति मुख्य कार्यपालन



अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। समिति की मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार होंगी कार्यस्थल पर उत्पीडन से संबंधित प्राप्त शिकायतों की विधिवत सुनवाई और निराकरण। समिति के सदस्यों की हर माह अनिवार्य बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लिखित मामलों की समीक्षा होगी। शासन की नीति के अनुरूप समिति द्वारा की गई कार्रवाई का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को भेजा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी विभागों से जानकारी संकलित कर शासन को भेजें और महिला नीति के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। इस समिति के गठन से उन महिलाओं को संभल मिलेगा, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं या उन संस्थानों में हैं जहाँ आंतरिक शिकायत समिति मौजूद नहीं है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और भयमुक्त कार्य वातावरण तैयार करना है।

करकेली वाड़ी परियोजना का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

उमरिया। जिले के बरही उजान क्षेत्र में नाबाई मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के अंतर्गत संचालित परियोजना करकेली वाड़ी परियोजना का कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया। परियोजना का क्रियान्वयन रिफ़क्ट संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर संस्था के परियोजना प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने परियोजना की विस्तृत जानकारी उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत 450 आदिवासी किसानों की बंजर भूमि पर प्रति किसान 30 आम (आठपाली प्रजाति) एवं 27 अमरुद (एल-49 प्रजाति) के पौध रोपित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 50 भूमिहीन आदिवासी किसानों को मुर्गी पालन एवं बकरी पालन के माध्यम से आजीविका सहयोग उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के तहत जल संरक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, अंतरवर्तीय फसल हेतु बीज वितरण तथा स्वास्थ्य शिविर जैसी गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के साथ कृषि आधारित रोजगार को भी प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला है।निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल आदिवासी समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में एक सशक्त एवं प्रेरणादायी मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।



मानपुर की कलंकित विरासत को गिली नई धार

कागजी फर्म और जातिवाद के गटजोड़ ने निगला कटार का बजट

उमरिया। जिले की जनपद पंचायत मानपुर, जो कभी अपने भ्रष्टाचार के कारनामों के लिए पूरे एशिया में कुख्यात रही है, आज फिर से उसी कलंकित इतिहास को दोहराने की राह पर है। इस बार भ्रष्टाचार का यह खेल ग्राम पंचायत कटार में देखने को मिल रहा है, जहां विकास की गंगा को कागजी फर्मों और भाई-भतीजावाद के गटर में बहा दिया गया है। ताजा मामला अवधलाल के घर के पास बनी उस पुलिया का है, जो बनने से पहले ही भ्रष्टाचार के मलबे में तब्दील हो चुकी है। यहां सरकारी खजाने की ऐसी निलंज बंदरबांट हुई है कि तंत्र की शुचिता पूरी तरह तार-तार हो गई है।

निर्माण सामग्री का तिलिस्म

कटार पंचायत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हथियार पीयूष ट्रेडर्स नाम की फर्म बनी है। सूत्रों और चर्चाओं की मानें तो यह फर्म महज एक छोटी सी किराना दुकान की आड़ में संचालित हो रही है, लेकिन पंचायत के रिकॉर्ड में यह रेत और गिट्टी की सबसे बड़ी सप्लायर बनी बैठी है। हैरत की बात यह है कि पंचायत के पास इस तथाकथित सप्लायर द्वारा दी गई सामग्री की एक भी रॉयल्टी रसीद उपलब्ध नहीं है। जब इस बारे में सवाल उठते हैं, तो सचिव महोदय बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं कि रॉयल्टी वेंडर के पास होगी। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है, बल्कि सीधे तौर पर राजस्व चोरी को संरक्षण देने जैसा है। सवाल यह है कि अगर पीयूष ट्रेडर्स ने अवैध उत्खनन की सामग्री सप्लाई नहीं की, तो रॉयल्टी रसीदें पंचायत के पोर्टल पर क्यों नहीं हैं।



पारदर्शिता को लगा पलीता

भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए शांतिराना तरीका अपनाया गया है। पीयूष ट्रेडर्स के जो बिल पंचायत में लगाए जा रहे हैं, वे इतने धुंधले और अस्पष्ट हैं कि यह पढ़ पाना भी मुश्किल है। कि फर्म वास्तव में किसके नाम पर पंजीकृत है। बताया जा रहा है कि यह फर्म संभवतः राम विनोद पटेल के नाम पर है। बिलों को जानबूझकर धुंधला रखना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्या इन बिलों की जांच कर यह देखा गया कि फर्म संचालक ने स्वयं यह सामग्री कहाँ से खरीदी है।

जातिवाद का सुरक्षा कवच और सचिव की भूमिका

कटार पंचायत के सचिव कपिल पटेल इस पूरी पटकथा के मुख्य खलनायक बनकर

उभरे हैं। आरोप है कि सचिव महोदय ने पंचायत को विकास की इकाई बनाने के बजाय अपनी निजी जागीर बना लिया है। जातिवाद को बढ़ावा देकर और अपने चहेते वेंडरों के साथ सांठ-गांठ कर, उन्होंने सरकारी पैसों का आहरण तो कर लिया, लेकिन धरातल पर गुणवत्ता शून्य है। पुलिया निर्माण के लिए पांचवें वित्त आयोग से स्वीकृत 2.86 लाख रुपये में से सामग्री मद की भारी-भरकम राशि अप्रैल महीने में ही पांच फर्जी बिलों के जरिए निकाल ली गई। यक्ष प्रश्न यह है कि जब पसीना बहाने वाले मजदूरों की मजदूरी अब तक बकाया है, तो तथाकथित वेंडर पीयूष ट्रेडर्स पर सचिव इतने मेहरबान क्यों हुए?

सरपंच का भाई बना सुपर सीएम

कटार पंचायत में महिला सशक्तिकरण के दावों की भी धजियां उड़ाई जा रही हैं। निर्वाचित महिला सरपंच रीता पटेल सिर्फ रबर स्टैंड बनकर रह गई हैं। चूंकि सरपंच के पति कालरी में नौकरी करते हैं और लंबे समय तक पंचायत से बाहर रहे, इस शून्य का लाभ उठाकर सरपंच के भाई ने पंचायत की कमान संभाल ली है। आज स्थिति यह है कि पंचायत में सरपंच का भाई समांतर शासन चला रहा है। आधिकारिक बैठकों से लेकर निर्माण कार्यों की देखरेख तक, हर जगह उसी का हस्तक्षेप है। चर्चा है कि निर्माण कार्यों को ऑफ-रिकॉर्ड ठेके पर देकर गुणवत्ता की बलि चढ़ाई जा रही है, और यह सब सचिव और उपयंत्री की मौन सहमति से हो रहा है।

कमीशनखोरी या लापरवाही

क्षेत्र के उपयंत्री का तकनीकी दायित्व था कि वे निर्माण की गुणवत्ता और रॉयल्टी की जांच करते, लेकिन यहां तो कमीशन के दलदल में उनकी कलम भी डूब चुकी है। बिना भौतिक सत्यापन और बिना मानकों की जांच किए बिल पास करना यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के इस संगठित गिरोह में ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं।

कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग

कटार ग्राम पंचायत में हो रही यह लूट-खसोट चीख-चोख कर कह रही है कि यहाँ विकास की नहीं, बल्कि विनाश की नींव रखी गई है। यदि जिला प्रशासन ने सचिव, सरपंच के भाई और पीयूष ट्रेडर्स के इस नापाक गटजोड़ की उच्चस्तरीय जांच नहीं कराई और फर्म की खरीदी-बिक्री के रिकॉर्ड नहीं खंगाले, तो सरकारी खजाने की यह डकैती जारी रहेगी। जनता की गाढ़ी कमाई को डकारने वाले इन सफेदपोशों के चेहरों से नकाब उतारना अब समय की मांग है। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा, जब जांच की आंच इन भ्रष्टाचारियों के घर तक पहुंचेगी।

इनका कहना है...

नौगवां के राम विनोद पटेल हैं, उनके पास दुकान भी है और रॉयल्टी भी है।

कपिल पटेल

सचिव

ग्राम पंचायत कटार

मा.वि. कन्या उमरिया का निरीक्षण किया गया, परीक्षा शांति पूर्वक एवं सुचारू रूप से संचालित होना पायी गयी। परीक्षा में किसी भी परीक्षा केन्द्र में नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुये, अतः नकल प्रकरण निरंक है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा व्यवस्था एवं संचालन मंडल के निर्देशानुसार उचित एवं व्यवस्थित पायी गयी, सभी परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल तैनात पाया गया। परीक्षा केन्द्रों पर 144 धारा लगाने के फलस्वरूप बाहय भीड़ एवं असमाजिक तत्वों की भीड़ नहीं दिखाई दी, परीक्षार्थे शांति पूर्ण संचालित पायी गयी।



खबर संक्षेप



हरी झण्डी दिखा कर प्रचार रथ को किया रवाना

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुसार मार्गदर्शन में 09 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 07 मई को प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल द्वारा हरी झण्डी दिखा कर प्रचार रथ को रवाना किया। उक्त प्रचार रथ के माध्यम से अनूपपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर नेशनल लोक अदालत के लाभों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर नरेंद्र पटेल प्रथम अपर जिला न्यायाधीश नोडल अधिकारी, श्रीकृष्ण डागलिया तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती चैनवती ताराम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावेन्द्र कुमार सोनी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठखण्ड एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर, सुश्री सुधा पाण्डेय न्यायाधीश, बाँबी सोनकर न्यायाधीश, सुश्री सृष्टि साहू न्यायाधीश, बृजेश पटेल जिला विधिक सहायता अधिकारी, संतदसा नापित चीफ लीगल एड डिफेंस कार्टिसिल अनूपपुर, रामकुमार राठौर सचिव जिला अभिभाषक संघ सहित न्यायालय के अधिकारी कर्मचारीगण, डिफेंस कार्टसेल्स एवं अधिकवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहें।

खनिज रेत का अवैध परिवहन करने पर 2 वाहन जब्त



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशन में खनिज विभाग अनूपपुर द्वारा तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम अमगवां तथा तहसील जैतहरी के ग्राम खोडोरी में खनिज रेत का अवैध परिवहन करने पर वाहन 2 मेटाडोर को जप्त कर वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमाुसार प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा नशामुक्ति विषय पर जागरूकता गोष्ठी का किया गया आयोजन



अनूपपुर। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा अनूपपुर द्वारा विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह के अंतर्गत 3 मई को वृद्धाश्रम में तथा 4 मई को आंगनबाड़ी केन्द्र पटौराटोला में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा 6 मई को जिला जेल अनूपपुर में नशामुक्ति विषय पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। वृद्धाश्रम में शिविर के दौरान सभी वृद्धजनों का एनसीडी परीक्षण किया गया तथा प्रत्येक वृद्धजन से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली गई। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्र पटौराटोला में आयोजित शिविर में 3 माह से 8 वर्ष तक के बच्चों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक परामर्श एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। जिला जेल अनूपपुर में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में नशे के दुष्प्रभावों, मानसिक एवं शारीरिक हानि तथा इससे परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही सभी को नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी अनूपपुर के पदाधिकारी उपस्थित थे।

टकहुली एवं मौहरी ग्राम में विशेष ग्राम सभा कर जंगली हाथियों से बचाव की की गई जन जागरूकता



हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जंगली हाथियों से बचाव के संबंध में जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत टकहुली तथा मौहरी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्राम सभा में जंगली हाथियों से बचाव तथा उससे संबंधित प्रमुख जानकारी दी गई। विशेष ग्राम सभा में ग्राम वासियों के साथ ही जनपद पंचायत जैतहरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके रैक्कार

सुप्रीम कोर्ट में गूंजा महेंद्र गोयनका का नाम

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सुनवाई से किया किनारा

सुप्रीम कोर्ट में गूंजा महेंद्र गोयनका का नाम न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सुनवाई से किया किनारा करोड़ों के कथित फर्जीबाई पर मचा सियासी मूचाल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

देश की सर्वोच्च अदालत में उस वक्त सनसनी फैल गई जब न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने महेंद्र गोयनका से जुड़े मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी दी कि “इस केस में कौन है महेंद्र गोयनका?” न्यायमूर्ति ने पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। दूसरी ओर, गोयनका पर सैकड़ों करोड़ के कथित वित्तीय घोटाले, फर्जी हस्ताक्षर, कंपनियों पर कब्जा, राजनीतिक संरक्षण और फरारी जैसे गंभीर आरोपों ने मध्यप्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है।

सुप्रीम कोर्ट में अचानक क्या हुआ? जज की टिप्पणी से मचा हड़कंप

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जैसे ही महेंद्र गोयनका से जुड़े प्रकरण की सुनवाई शुरू हुई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने मामले पर असंतोष जाहिर करते हुए खुद को इससे अलग कर लिया। अदालत में की गई उनकी टिप्पणी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कानूनी हलकों में इसे बेहद असामान्य घटनाक्रम माना जा रहा है। अब यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद पूरे मामले ने और अधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक संवेदनशीलता हासिल कर ली है।

फर्जी हस्ताक्षर, कंपनियों पर कब्जा और करोड़ों की कथित हेराफेरी

महेंद्र गोयनका पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षरों और दस्तावेजों के जरिए कई कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। आरोपों के अनुसार, यह पूरा मामला सैकड़ों करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं, कंपनी के बिके हुए माल को



कथित रूप से छल-कपट से बेचने और कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। कोलकाता में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। कटनी में भी 420, 467, 468 और 471 जैसी धाराओं के तहत अलग-अलग मामले दर्ज बताए जा रहे हैं।

डेढ़ साल से फरार? पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जानकारी के अनुसार, गोयनका से जुड़े कुछ सहयोगियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी

हैं। इसके बावजूद आरोप है कि पिछले डेढ़ से दो वर्षों से संबंधित आरोपी गिरफ्तारी से बाहर हैं। इससे मध्यप्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी हलकों में चर्चा है कि आखिर इतने गंभीर मामलों में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? क्या प्रभावशाली संरक्षण के कारण कार्रवाई धीमी रही? यह सवाल अब जनचर्चा का विषय बन चुका है।

राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से गरमाई सियासत

मामले ने नया मोड़ तब लिया जब गोयनका की कथित

मां नर्मदा के आशीर्वाद के साथ भारती ने संभाला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष पद का कार्यभार

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक।

पवित्र तीर्थनगरी अमरकंटक में 7 मई गुरुवार को अमरकंटक विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र भारती ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। अमरकंटक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुष्पराजगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसीम अहमद भट्ट ने उन्हें औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण कराया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजेंद्र भारती ने विश्व प्रसिद्ध आस्था केंद्र श्री नर्मदा मंदिर में विधि-विधान से विशेष पूजन-अर्चन कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेश एवं क्षेत्र की सुख-समृद्धि, विकास और जनकल्याण की कामना करते हुए सेवा एवं समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में भी भगवान का पूजन-अर्चन किया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अमरकंटक विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित गरिमामयी समारोह में उन्होंने विधिवत पदभार संभाला। इस



अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर उनका आत्मीय स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का वातावरण बना रहा। अपने संबोधन में राजेंद्र भारती ने कहा कि अमरकंटक केवल एक नगर नहीं, बल्कि

भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना एवं प्रकृति का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाएंगे। अमरकंटक को स्वच्छ, व्यवस्थित, सुंदर एवं पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित बनाना हेतु जनसहभागिता

के साथ योजनाएं संचालित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं एवं सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि राजेंद्र भारती के नेतृत्व में अमरकंटक विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक गरिमा और मूल पहचान को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर रामलाल रौतेल, वसीम अहमद भट्ट, पार्वती सिंह, कमल प्रताप सिंह, आशुतोष अग्रवाल, मिथिलेश पयासी, रामगोपाल द्विवेदी, रोशन पनारिया, धनेश द्विवेदी, अंजना कटारे, भानु प्रसाद सेन तथा ज्ञान दास पनिका सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को रामगोपाल द्विवेदी, मिथिलेश पयासी, रामलाल रौतेल तथा राजेंद्र भारती ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सूरज साहू ने किया।



कलेक्टर ने किसान प्रेमलाल केवट इंटीग्रेटेड फार्मिंग कार्य का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बुधवार को जिले के भ्रमण के दौरान जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत भाद पहुंचकर किसान प्रेमलाल केवट द्वारा किए जा रहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग आधारित कृषि कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रॉबेरी, बरबटी, खरबूजा सहित विभिन्न फसलों की खेती एवं सिंचाई व्यवस्था का अवलोकन कर किसान से विस्तारपूर्वक चर्चा की। कलेक्टर श्री पंचोली को किसान प्रेमलाल केवट ने बताया कि वे

इंटीग्रेटेड फार्मिंग पद्धति के तहत उद्यानिकी विभाग से प्राप्त ड्रिप मशीन के माध्यम से ड्रिप सिंचाई अपनाकर स्ट्रॉबेरी, बरबटी एवं अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सीजन में स्ट्रॉबेरी उत्पादन से लगभग 70 से 80 हजार रुपए तथा बरबटी से लगभग 20 हजार रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। कलेक्टर श्री पंचोली ने किसान की प्रगतिशील सोच एवं नवाचार आधारित खेती की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि

जिले के अधिक से अधिक किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तथा किसानों को खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, सहायक संचालक उद्यानिकी सुरेंद्र सिंह श्याम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

तथा पेसा के जिला समन्वयक एवं ब्लॉक समन्वयक उपस्थित थे। ग्राम सभा के दौरान ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समिति के कार्यों के संबंध में सदस्यों को अवगत कराया गया स्थानीय सरपंच, पंच और ग्रामीणों को हाथी मानव द्वन्द्व को रोकने के संबंध में सतर्कता, बचाव आदि की जानकारी देते हुए जनजागरूकता के लिए प्रेरित किया गया।